

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या -133/2023

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं. बनाग् प्रदीप कुमार गुप्ता वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई^१
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

२५/०३/२५

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं. द्वारा Under Section-14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत क्रमांकता 1. Pradeep Kumar Gupta, R/o 27 Koyari Tola, Near Bajrang Bali Mandir, Ramgarh Cantt, Urban, Ramgarh, Dist-Ramgarh 2. Dukhan Saw, R/o 27 Koyari Tola, Near Bajrang Bali Mandir, Ramgarh Cantt, Urban, Ramgarh, Dist-Ramgarh के विलद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या-4987, दिनांक-22.09.2010 से हासिल भूमि मौजा-रामगढ़ थाना नं०-82 थाना-रामगढ़ खाता नं०-130, प्लॉट नं०-27/23, रकवा-08 डिसमील चौहदी उ०-रघु नन्दन साहु, द०-रास्ता, पु०-रास्ता, प०-दुखन साहु तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए क्रम प्राप्त कर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं. के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निबंधन केवाला संख्या-4987, दिनांक-22.09.2010 से हासिल भूमि मौजा-रामगढ़ थाना नं०-82 थाना-रामगढ़ खाता नं०-130, प्लॉट नं०-27/23, रकवा-08 डिसमील चौहदी उ०-रघु नन्दन साहु, द०-रास्ता, पु०-रास्ता, प०-दुखन साहु तथा भूमि पर बनी संरचना के Mortgage के एवज में विपक्षी को दिनांक-31.05.2019 की तिथि में 32,25,000/- (बत्तीस लाख पचीस हजार) रु० का क्रम 15 वर्षों के लिए दिया गया। जिसका किस्त अदा नहीं करने के कारण दिनांक-22.09.2020 के गणना के अनुसार दिए गए क्रम के मूलधन ब्याज सहित 34,52,555/- (बत्तीस लाख बवन हजार पाँच सौ पचपन) रु० हो गया। उधारकर्ता द्वारा मूलधन राशि व ब्याज की राशि के भुगतान में चूक के कारण, उधारकर्ता के खाते को N.P.A घोषित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक-31.03.2011 को ज्ञानी टिक्का-नितेश्वरों के अनुसार SARFAESI Act की धारा-13

वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया, जिसके तहत उधारकर्ता को नोटिस के 60 दिनों के भीतर बैंक को बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया। उपरोक्त नोटिस में दी गई निर्धारित 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी उधारकर्ता अपनी देयता का भुगतान करने में विफल रहा है। फलस्वरूप SARFAESI Act, 2002 की धारा-13 की उपधारा-(4) के अंतर्गत ऋण की वसूली के उद्देश्य से उक्त परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण लेने का निर्णय लिया गया है, ताकि संपत्ति को बिक्री कर सकल खरीदार को हस्तांतरण कर सकें। उल्लेखनीय है कि SARFAESI Act, 2002 अधिनियम-14 (1) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को भौतिक कब्जा लिए जाने हेतु अधिकृत कर सकता है। विषयगत मामले के संबंध में Bombay High Court judgment in case of M/s Trade Well & others V/s Indian Bank in Cr WP No. -2767 of 2006 में पीठासीन पदाधिकारी को केवल दो पहलुओं पर विचार किए जाने का आदेश पारित किया गया है। 1. क्या सुरक्षित परिसंपत्ति उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है अथवा नहीं। 2. N.P.A अधिनियम की धारा-13(2) के तहत उधारकर्ता को नोटिस दिया गया है या नहीं। बैंक द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

उक्त के आलोक में हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिंग के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा परिसंपत्ति पर भौतिक कब्जा प्राप्त किए जाने निमित सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विषयगत बाद में विपक्षी के द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष को माननीय न्यायालय के रामक्ष प्रथम पक्ष द्वारा दायर SARFAESI अधिनियम-2002 की धारा-14 (1) के तहत दायर आवेदन के मामले में दिनांक-12.12.2023 को उपस्थित होने के लिए रूचित किया गया। उपरोक्त आवेदन की प्रति द्वितीय पक्ष को उपलब्ध नहीं की गई है, इसलिए इसके अभाव में द्वितीय पक्ष इसका उचित उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष से ऋण के लिए आवेदन किया था और केवल 32,25,000/- (बत्तीस लाख पच्चीस हजार रुपये) की ऋण राशि प्राप्त की थी, और जनवरी-2020 तक लगातार अपनी किरत का भुगतान किया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण द्वितीय पक्ष के व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ और इसके लिए विपक्षी पक्ष आगे भुगतान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है जब वह अपने व्यवसाय से अपने नुकसान की भरपाई करेगा। मौजा-रामगढ़ थाना संख्या-82, खाता संख्या-130, प्लॉट संख्या-27/23 रकवा-0.8 डी० जिला-रामगढ़ का विलेख जो उपरोक्त ऋण के संबंध में बंधक के रूप में उपयोग किया जा रहा है, प्रियंका देवी की है। द्वितीय पक्ष प्रश्नगत संपत्ति का स्वामी नहीं है। उक्त संपत्ति की वास्तविक स्वामी प्रियंका कुमारी है। जो

जमा नहीं की है। इसके लिए उक्त भूमि के वार्तविक स्वामी मौजा-रामगढ़ थाना-रामगढ़ थाना संख्या-82, खाता संख्या-130, प्लॉट संख्या-27/23 रकवा-0.8 डी० जिला-रामगढ़ द्वारा SARFAESI अधिनियम-2002 की धारा-17 की उपधारा-1,2,3 के तहत (DRT) DEBTS Recovery Tribunal, Ranchi में वाद संख्या-25/2021 के तहत मामला दायर किया जा चुका है। प्रथम पक्ष राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम-1987 की धारा-29 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

उक्त के आलोक में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विषयगत वाद में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक-106, दिनांक-13.01.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-रामगढ़ थाना संख्या-82 के अन्तर्गत खाता संख्या-130, प्लॉट संख्या-2723 रकवा-0.08 ए० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ संख्या-126/34 में प्रदीप कुमार गुप्ता, पिता-दुखन साव के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या-1320/10-11 अंचल अधिकारी, रामगढ़ के आदेशानुसार स्वीकृत की गई है। उक्त भूमि प्रदीप कुमार गुप्ता को केवल संख्या-4987 दिनांक-22.09.2010 के द्वारा खरीदगी प्राप्त है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under Sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। बैंक के द्वारा ई-नीलामी बिक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप SARFAESI Act, 2002 की धारा-14 के तहत ऋणकर्ता से संबंधित सम्पत्ति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है, जो विधिवत एवं न्याय-संगत है। बैंक द्वारा दखल कब्जा के संबंध में किये गये अनुरोध को स्वीकार करने योग्य तथा विधि-संगत है।

निष्कर्ष :-

U/s -14 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं० से प्राप्त आवेदन एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अबलोकन किया तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना स्पष्ट है कि :-

1 हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं० द्वारा पूर्व में Recall Notice Under Section-13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत ऋणकर्ता को किया गया। Bombay High Court judgment in case of M/s Trade Well & others V/s Indian Bank in Cr WP No. - 2767 of 2006 clearly lays down as follows :- "In our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA Act, the CMM/DM will have to consider only two aspects, he must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction

2 हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिंग द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से रघुनाथ है कि ऋण प्राप्त कर्ता के द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में सकारात्मक पहल नहीं की गई है। बल्कि प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी के नाम से दिनांक—26.04.2018 को निष्पादित अनिबंधित Sale Deed Agreement के आधार पर प्रश्नगत भूमि का भू-स्वामी होने के इन्कार किया जा रहा है, जो SARFAESI Act, 2002 की प्रक्रिया से बचने हेतु न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास प्रतीत होता है।

3 अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में Mortgage भूमि की प्रकृति के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है, जिसके जमाबंदी रैयत प्रदीप कुमार गुप्ता, पिता—दुखन साव है।

आदेश :-

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के प्राप्त मन्त्रव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट—2002 की धारा—14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत विज्ञ अधिवक्ता, हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिंग के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला संख्या—4987, दिनांक—22.09.2010 से हासिल भूमि मौजा—रामगढ़ थाना नं०—82 थाना—रामगढ़, खाता नं०—130, प्लॉट नं०—27/23, रकवा—08 डिसमील चौहदादी उ०—रघु नन्दन साहु, द०—रास्ता, पु०—रास्ता, प०—दुखन साहु) को जप्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिंग को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि—व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यदाही बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

*Chandan
25/03/25*
उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

*Chandan
25/03/25*
उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।